गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 306
दि. 10.03.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को अदालत से 10 दिन की अंतरिम जमानत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वर्ष 2020 के बहुचर्चित 2020 Delhi Riots मामले में आरोपी Sharjeel Imam को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने यह राहत मानवीय आधार पर देते हुए उन्हें अपने परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण कारणों के चलते 10 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी है।

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Sameer Bajpai की अदालत ने आदेश दिया कि शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है। अदालत ने यह फैसला उनकी ओर से दायर उस अर्जी पर सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह राहत दी।

सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकीलों ने अदालत के सामने कई दलीलें रखीं। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल के सगे भाई की शादी होने वाली है और परिवार में इस महत्वपूर्ण अवसर पर उनकी मौजूदगी बेहद जरूरी है। इसके अलावा अदालत को यह भी बताया गया कि उनकी मां की तबीयत काफी समय से खराब चल रही है और घर में उनकी देखभाल करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि इन मानवीय परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें कुछ दिनों के लिए अंतरिम राहत दी जाए।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने शरजील इमाम को सीमित अवधि के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति प्रदान कर दी। हालांकि यह राहत केवल दस दिनों के लिए दी गई है और निर्धारित समय पूरा होने के बाद उन्हें फिर से जेल में लौटना होगा।

यह मामला वर्ष 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। उस समय नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। दिल्ली के कुछ इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गए थे। इस हिंसा में कई स्थानों पर आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पें हुईं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और कई लोगों की जान भी चली गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस हिंसा में कुल 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

दिल्ली पुलिस के अनुसार उस समय विभिन्न संगठनों और समूहों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे थे। पुलिस का आरोप है कि इन प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया और कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो गई। पुलिस ने इन घटनाओं की जांच के बाद कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

इसी संदर्भ में शरजील इमाम का नाम भी सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में दावा किया था कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और उन्हें व्यापक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस के अनुसार उस समय दिल्ली के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन को संगठित करने और लोगों को जुटाने के लिए अलग-अलग स्तर पर बैठकें और अभियान चलाए गए थे।

दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी दावा किया गया कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान राजधानी के कई हिस्सों में पर्चे बांटे गए और लोगों को विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस के अनुसार पांच दिसंबर को Jawaharlal Nehru University परिसर में अल्पसंख्यक संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्रों की बैठक हुई थी, जिसमें आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई थी।

पुलिस के आरोप पत्र में यह भी कहा गया कि इसके अगले दिन दिल्ली के ओखला, निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में कैब के माध्यम से हजारों पर्चे बांटे गए। इन पर्चों के जरिए लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस तरह की गतिविधियां केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थीं, बल्कि कई अन्य शहरों और कस्बों तक भी इसका प्रभाव पहुंचा था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जांच के दौरान दिए गए बयान में कहा था कि शरजील इमाम के कथित बयानों और अन्य साक्ष्यों को साजिश से जुड़े आरोप पत्र का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि इन सब तथ्यों के आधार पर यह जांच की गई कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन संगठित किए गए और बाद में वे हिंसा में कैसे बदल गए।

दूसरी ओर, इस मामले में आरोपित कई लोगों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और अदालत में अपने बचाव में दलीलें दी हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई अभी भी अदालत में जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है।

फिलहाल अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के कारण शरजील इमाम को सीमित अवधि के लिए राहत मिल गई है। उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी मां की देखभाल करने के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई है। निर्धारित समय पूरा होने के बाद उन्हें फिर से न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा और मामले की आगे की सुनवाई अदालत में जारी रहेगी।

असम की राजनीति में हलचल: एजीपी नेता जयंत खाउंड कांग्रेस में शामिल

(जीएनएस)। गुवाहाटी। असम में अगले विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय दल Asom Gana Parishad को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता Jayanta Khound ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम को राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी चुनावों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम असम की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है और इसका असर आने वाले चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। जयंत खाउंड ने सोमवार को नई दिल्ली में औपचारिक रूप से Indian National Congress की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें असम कांग्रेस के अध्यक्ष Gaurav Gogoi, पार्टी के प्रदेश प्रभारी Jitendra Singh और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar शामिल थे। इन नेताओं की मौजूदगी ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। खाउंड के साथ उनके कई समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके इस फैसले का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर

तक सीमित नहीं है बल्कि उनके समर्थक वर्ग पर भी इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने इस मौके को पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि जयंत खाउंड लंबे समय से पार्टी के संपर्क में थे और अब उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होकर असम की जनता की सेवा के लिए काम करने का संकल्प लिया है। पार्टी का मानना है कि खाउंड के अनुभव और उनके जनाधार से कांग्रेस को विशेष रूप से ऊपरी असम के क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। इन इलाकों में लंबे समय से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा है और कांग्रेस इस प्रभाव को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रही है। जयंत खाउंड के पार्टी छोड़ने को Asom Gana Parishad के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। असम गण परिषद लंबे समय से राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल के रूप में सक्रिय रही है और कई मौकों पर उसने राज्य की सत्ता में भी भागीदारी निभाई है। ऐसे में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का चुनाव से पहले अलग होना संगठन के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य की मौजूदा सरकार पर भी तीखे राजनीतिक हमले किए। असम कांग्रेस के अध्यक्ष Gaurav Gogoi ने राज्य के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma को निशाने पर लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है और राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है और लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। गोगोई ने यह भी कहा कि असम की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा।

कांग्रेस महासचिव Jitendra Singh ने भी इस अवसर पर भाजपा और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य के क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह प्रयास इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हो जाए और भाजपा का प्रभुत्व स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और उन्हें समाप्त करने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जितेंद्र सिंह ने जयंत खाउंड का स्वागत करते हुए उन्हें असम की सांस्कृतिक पहचान का मजबूत समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि खाउंड लंबे समय से असमिया समाज और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस असम की पहचान, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी समान विचारधारा वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जयंत खाउंड का कांग्रेस में शामिल होना केवल एक साधारण राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह असम की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की बड़ी तैयारी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजनीति में एक नया संवैधानिक विवाद उभरता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी तेज कर दी है। इस कदम को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक टकराव के रूप में देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और अन्य कई विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने संवैधानिक पद की गरिमा और निष्पक्षता से समझौता किया है।

सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर आपसी चर्चा के बाद महाभियोग प्रस्ताव का मसौदा लगभग तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह केवल किसी एक राजनीतिक दल की पहल नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन INDIA Alliance के कई दलों की सामूहिक रणनीति का हिस्सा है। इस कदम के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता को लेकर अपने आरोपों को संसद के मंच पर उठाना चाहता है। इस प्रस्ताव की तैयारी को लेकर विपक्ष के नेताओं के बीच लगातार संपर्क और बैठकें हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—में सांसदों से हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विपक्ष का उद्देश्य जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन जुटाकर महाभियोग का नोटिस संसद में पेश करना है।

इस पूरे घटनाक्रम के संकेत पहले ही सामने आ चुके थे जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि अगर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं तो लोकतंत्र के लिए यह चिंता का विषय है। अब विपक्षी दलों की ओर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी उसी बयान के बाद की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था लोकतंत्र की रीढ़ होती है और इसकी निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। उनका आरोप है कि हाल के कुछ फैसलों और कार्यप्रणाली ने इस संस्था की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। इसी कारण विपक्ष ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है।

महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और जटिल मानी जाती है। संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही होती है जैसी Supreme Court of India या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है। इसका अर्थ यह है कि केवल गंभीर आरोप सिद्ध होने की स्थिति में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

इस प्रक्रिया के तहत संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए पहले एक लिखित नोटिस देना पड़ता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर इस नोटिस पर होना अनिवार्य होते हैं। विपक्ष का दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है और वे अगले एक सप्ताह के भीतर आवश्यक हस्ताक्षर जुटाकर यह नोटिस सदन में पेश कर सकते हैं। हालांकि यह दावा राजनीतिक स्तर पर है और वास्तविक स्थिति का पता नोटिस पेश होने के बाद ही चल सकेगा।

यदि नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद एक जांच समिति गठित की जाती है। यह समिति लगाए गए आरोपों की गहराई से जांच करती है और यह तय करती है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। जांच के बाद यदि समिति यह मानती है कि आरोप गंभीर हैं और उनमें पर्याप्त आधार है, तभी मामला आगे बढ़ता है और संसद में उस पर चर्चा होती है।

इसके बाद प्रस्ताव को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का अर्थ है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें। साथ ही कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना जरूरी होता है। इस कारण महाभियोग प्रस्ताव को पारित कराना किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के लिए बेहद कठिन माना जाता है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए विपक्ष के सामने यह चुनौती और भी बड़ी दिखाई देती है। संसद में सत्ता पक्ष के पास मजबूत संख्या बल है, ऐसे में यदि सरकार इस प्रस्ताव का विरोध करती है तो इसे पारित कराना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य केवल संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करना ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक बहस को भी तेज करना हो सकता है।

दूसरी ओर सत्ता पक्ष इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देख सकता है। सरकार के समर्थक दलों का मानना है कि विपक्ष द्वारा इस तरह का कदम उठाना संवैधानिक संस्थाओं को अनावश्यक विवादों में घसीटने जैसा है। उनका तर्क हो सकता है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।

फिलहाल यह मामला राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टि से बेहद संवेदनशील बन गया है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर तीखी बहस होने की संभावना है। यदि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस पेश करता है तो यह देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम होगा। इससे न केवल संसद की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है, बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी निष्पक्षता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा भी शुरू हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि विपक्ष कब और किस रणनीति के तहत यह प्रस्ताव संसद में लाता है और उस पर आगे क्या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होती है। आने वाले समय में यह मुद्दा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बहस का केंद्र बन सकता है।

ब्राज़ील में अनोखा कानून: कैदियों की सज़ा कम की जाएगी अगर वे जेल में किताबें पढ़ते हैं, पुनर्वास के लिए नई पहल

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। जब हम पढ़ने के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगाते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और सरकार लोगों के पढ़ने-लिखने के लिए बजट आवंटित करती है, तो ब्राज़ील में एक अनोखा कानून है। अगर कोई कैदी जेल में एक साल में 12 किताबें पढ़ता है और उन पर नोट्स लिखता है, तो उसकी सज़ा में 48 दिन की कटौती कर दी जाती है। क्योंकि ब्राज़ील में, कैदियों के पुनर्वास से उन्हें जीवन में फिर से स्थापित होने में आसानी होती है। एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत कैदियों को जेल में पढ़ाई करने, कुछ सीखने और ज्ञान प्राप्त करके खुद को समृद्ध करने पर उनकी सज़ा में छूट दी जाती है।

शून्य त्रुटि एजेंसी

इस कार्यक्रम के तहत, कैदी साहित्य, विज्ञान या दर्शन पर 12 पुस्तकें पढ़ सकते हैं और प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें उस पुस्तक के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है। यदि निदेशकों को यह टिप्पणी उपयुक्त लगती है, तो प्रत्येक पुस्तक के लिए उनकी सजा में 4 दिन की कटौती का प्रावधान है। प्रति वर्ष 12 पुस्तकों के आधार पर, कैदी एक वर्ष में अपनी सजा में 48 दिन यानी डेढ़ महीने से अधिक की कटौती कर सकते हैं।

जेल की इस पहल को नागरिक समाज का व्यापक समर्थन मिला है क्योंकि यह जेल में सजा काट रहे कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। खतरनाक अपराधियों के साथ जेल में रहना, तनावपूर्ण और भीड़भाड़ वाले वातावरण में लंबे समय तक रहना थका देने वाला होता है और व्यक्तित्व को बदल देता है। हालांकि, अगर उनका मन कुछ रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधियों में लगा रहे, तो जेल से बाहर आने के बाद का जीवन आसान हो जाता है।

भारत में भी मुंगावली की खुली जेल को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ब्राजील के इस प्रयोग को भारत में भी आजमाना उचित होगा, जहां कैदी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।

महाशक्ति बनने के सपनों के बीच, शिक्षा, स्वास्थ्य और समान वेतन सहित समावेशी विकास की आवश्यकता है।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। एक ओर हम अपने देश को महाशक्ति बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन जब समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल या शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहता है, तो इन मुद्दों को भी विकास की हमारी परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। हम समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक समाधानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्थानीय समाधानों पर ध्यान नहीं देते।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

क्या हम बड़े शहरों के पास बसे गांवों की हालत से अनजान हैं? क्या हम शहर के भीतर ही झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं से भी अनभिज्ञ हैं? हमारे विचारकों के बीच आम आदमी तक बुनियादी ज़रूरतें पहुंचाने के प्रयासों पर गरमागरम बहस चल रही है। जिसमें कहा गया है कि पहले देश का आर्थिक विकास होना चाहिए। एक ऐसी बुनियादी ढांचा प्रणाली बनाई जानी चाहिए जिससे धन का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग हो सके। हम टंकी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पाइप में रिसाव हो तो पानी पौधों तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसी तरह, हम जीडीपी को कितना भी बढ़ा लें, अगर एचडीआई (मानव विकास सूचकांक) बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है, तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। श्रमिकों और औद्योगिक घरानों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं हैं। औद्योगिक घरानों को लचीले श्रम कानूनों की आवश्यकता है। आज, उद्योग स्थायी श्रमिकों के बजाय संविदा श्रमिकों को काम पर रखते हैं। उनके अधिकारों की अनदेखी की जाती है। कुछ देशों में संविदा श्रमिकों को नियमित श्रमिकों से अधिक वेतन दिया जाता है। हमें "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। संविदा श्रमिकों के नाम पंजीकृत होने चाहिए। उनके मौलिक अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। कॉर्पोरेट संस्कृति में न्यास की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। समावेशी विकास की दिशा अपनाएं जिसमें जनता, पर्यावरण और उपभोक्ता का ध्यान रखा जाए। केवल लाभ-उन्मुख और शेयरधारक-उन्मुख व्यावसायिक नीतियों को बदलें। पश्चिमी देशों में कॉरपोरेट जगत जनता का विश्वास खो चुका है। बैंकों और बड़ी कंपनियों को जनता के कर के पैसे से बचाया जा रहा है। आज लोकतंत्र उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कंपनियों के आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी की मांग कर रहा है ।

संपादकीय

बढ़ता तापमान

हाल के वर्षों में मौसम के मिजाज में जो तीव्र और असामान्य परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वे केवल सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं हैं बल्कि एक बड़े पर्यावरणीय संकट की ओर संकेत करते हैं। पहले उत्तर भारत में सर्दी का मौसम लंबा और अपेक्षाकृत स्थिर रहता था। दिसंबर से फरवरी तक ठंड का प्रभाव बना रहता था और उसके बाद धीरे-धीरे वसंत ऋतु का आगमन होता था, जो मौसम को संतुलित बनाते हुए गर्मी की ओर ले जाती थी। किंतु अब यह पारंपरिक चक्र तेजी से बदल रहा है। सर्दी की अवधि लगातार कम होती जा रही है और मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी का प्रभाव महसूस होने लगा है। कई क्षेत्रों में फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही तापमान अचानक बढ़ जाता है। वसंत ऋतु जैसे लगभग लुप्त होती जा रही है और सीधे गर्मी का मौसम दस्तक देने लगता है। यह बदलाव केवल मौसम की सामान्य प्रवृत्ति नहीं बल्कि क्षेत्रीय वायुमंडलीय परिवर्तनों और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा, तेजी से हो रहा औद्योगीकरण और जंगलों की कटाई जैसे कारक इस परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे सूर्य की गर्मी पृथ्वी के वातावरण में अधिक समय तक बनी रहती है। परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ता जा रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। इसका प्रभाव भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर विशेष रूप से दिखाई देने लगा है। मौसम में यह असामान्य परिवर्तन केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आजीविका पर भी व्यापक असर डाल रहा है।

विशेष रूप से उत्तर भारत के कृषि क्षेत्र में इसके नकारात्मक आर्थिक परिणामों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर गतिविधि है और जब मौसम का स्वाभाविक चक्र ही असंतुलित हो जाए तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। गेहूं, चना, सरसों और अन्य रबी फसलों को ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। जब मार्च की शुरुआत में ही तापमान तेजी से बढ़ने लगता है तो फसलों के दाने भरने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इससे उत्पादन में गिरावट आती है और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार असमय गर्मी के कारण फसल समय से पहले पक जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसके अलावा मौसम के असंतुलन से कीट और रोगों की समस्या भी बढ़ने लगी है, जो कृषि उत्पादन के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रही है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों की बागवानी पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हिमालयी राज्यों में सेब की खेती लंबे समय से स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिए सेब की बागवानी पर निर्भर हैं। किंतु हाल के वर्षों में कम होती ठंडक और तापमान में असामान्य वृद्धि के कारण सेब के बागों में उत्पादकता घटने लगी है। सेब के पेड़ों को एक निश्चित अवधि तक ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में "चिलिंग आवर" कहा जाता है। यदि यह अवधि पर्याप्त नहीं होती तो पेड़ों पर फूल और फल ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इसके परिणामस्वरूप न केवल उपज कम होती है बल्कि फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में सेब की खेती पारंपरिक क्षेत्रों से धीरे-धीरे ऊंचे पहाड़ी इलाकों की ओर खिसक सकती है। यह परिवर्तन स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में कृषि और बागवानी क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। किसानों को ऐसी फसलों और किस्मों को अपनाने की जरूरत होगी जो अधिक तापमान और कम जल उपलब्धता की स्थिति में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। सूखा-सहिष्णु फसलों को बढ़ावा देना, कम पानी में खेती की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियां कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा, ताकि भविष्य में संभावित जल संकट से निपटा जा सके।

दिल्ली के दिल में छाई अजीब खामोशी पर उठते प्रश्न

"विदेश नीति में आत्मनिर्भरता देश के वजूद का आधार बनी हुई है। ऐसे में ईरान और अमेरिकी-इस्राइल युद्ध की कुछ घटनाओं पर खामोशी सवालों के घेरे में है। नीति नियंताओं द्वारा आत्मनिर्भरता की नीति के बखान के बावजूद ईरान में लड़कियों के स्कूलों पर बमबारी करने वाली ताकतों संग बिना विचारे तालमेल से गुरेज करना चाहिये।"

अमेरिकियों ने बीच समुद्र फंसे रूसी तेल को खरीदने के वास्ते लिए भारत को 30 दिन की छूट दे दी है। यह वो संदेश है जो बीते शुक्रवार सुबह-सुबह ट्रंप प्रशासन की ओर से आया।

अभी यह स्पष्ट नहीं कि मोदी सरकार को ट्रंप प्रशासन के इन निर्देशों से चिढ़ हुई अथवा नहीं, क्योंकि उसे बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें यह भी शामिल है कि किससे तेल खरीदना है, कितना खरीदना है, और कब शुरू या बंद करना है। याद करें कि पिछले महीने ही, जब ट्रंप ने व्यापार समझौते के हिस्से के तौर पर घोषणा की थी कि भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार पर लगाया गया 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क हटा रहे हैं, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि यदि भारत फिर रूसी तेल खरीदने लगेगा, तो यह शुल्क दुबारा लागू हो जाएगा। और इसलिए, करीब हफ़्ता पहले ईरान संकट शुरू होने के बाद से मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर जो बहसें चल रही हैं, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने दखल दिया, उसमें आत्मनिर्भरता के इस नवीनतम प्रारूप को बतौर राष्ट्र नीति का साधन बरतने पर प्रश्न उठ रहे हैं।

विदेश मंत्रालय अपनी जिस 'व्यावहारिक नीति' की बहुत बड़ाई करता रहता है, शायद उसके तहत मानता है कि उसको दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहिए, और इसलिए ईरान पर बमबारी के मामले में उसके साथ चलना बेहतर है। इस नजरिये से तो भारतीयों को ब्रिटिश राज के खिलाफ़ स्वतंत्रता आंदोलन कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि, याद रहे कि उनके राज में, ट्रेनें हमेशा समय पर चलती थीं, सबके लिए शिक्षा शुरू की गई थी और सती जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगा दी गई थी।

कुछ अन्य लोग कहेंगे कि आत्मनिर्भरता का मतलब वास्तव में कुछ और है। यह जागरूक बने रहने, दुनिया की जटिलताओं को समझने, ज़रूरत पड़ने पर अलग-अलग पक्ष चुनने का निरंतर संघर्ष है- हकीकत में, सभी पक्षों के साथ तालमेल रखना पड़ता है, क्योंकि तभी तो आप अपने देश के हितों की रक्षा कर सकेंगे। (जवाहरलाल नेहरू ने इसे 'गुटनिरपेक्षता' कहा था, चलिए इस पर बहस किसी और दिन)।

सच तो यह कि भारत को वैश्विक राजनीति की नित बदलती बिसात का फ़ायदा उठाने का तगड़ा अनुभव है। इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि भारत इतना खुलकर ट्रंप और बीबी नेतन्याहू, दोनों के साथ, क्यों खड़ा है। इस्राइलियों ने आधे यूरोप को नाराज़ कर रखा है और ट्रंप हर दूसरे दिन पाकिस्तान को लुभाने की कोशिश करते हैं। इस बीच, ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन महीने में कम से कम एक बार परस्पर बात करते हैं- तब भी, जब अमेरिका भारत को रूसी तेल न खरीदने को धमका रहा था। ट्रंप चीन दौरे की जल्द ही, कम से कम ईरान संकट से पहले, योजना बना रहे थे-लेकिन बताया जा रहा है ईरान का साथी और सहयोगी चीन, अब ट्रंप और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है।

इसीलिए आत्मनिर्भरता का मतलब है समझदारी से चुनना, कुछ करना या न करते हुए देशहित में काम करना। इसका अभिप्राय था इस्राइल का अपना दौरा टालना, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि पूरी दुनिया, जिसमें आप भी शामिल हैं, जानती थी कि युद्ध होने वाला है; इसलिए नहीं कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं, बल्कि इसलिए कि भारत के कुल तेल आयात का 44 प्रतिशत हिस्सा ईरानी नियंत्रण वाले जलक्षेत्र होर्मुज़ जलसंधि से होकर आता है। इसका अर्थ था कि अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन ज़ायद को फोन करने से बचना, जिनकी इन दिनों अपने कभी के सबसे अच्छे दोस्त रहे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत बंद हैं- सिर्फ इसलिए नहीं कि आप दोनों से तेल खरीदते हैं या पाकिस्तान सऊदी अरब का रणनीतिक साझेदार है, बल्कि इसलिए कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में भारतीय आप्रवासी रहते हैं, यूएई में 40 लाख और सऊदी में लगभग 25 लाख।

इसका मतलब था कि सोनिया गांधी द्वारा इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी पर सवाल उठाने का इंतज़ार नहीं करना- उनकी हत्या के पांच दिन बाद आखिर विदेश सचिव विक्रम मिसरी को महज़ 2 किमी दूर दिल्ली में स्थित ईरान दूतावास पहुंचने का आदेश दिया गया, जहां उन्होंने भारत की ओर से शोक पुस्तिका पर संदेश लिखा। इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अंततः अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची को फोन किया। शुक्रवार शाम, इस्राइली विदेश मंत्री ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो 48 घंटे पूर्व ही इस्राइल से निकले थे, को पता नहीं था कि इस्राइल-अमेरिका ईरान पर कब बमबारी करने वाले हैं। अब इस्राइल की इस स्वीकारोक्ति पर दो तरह की प्रतिक्रिया सोच सकते हैं। पहली, इस्राइली कैसे दोस्त हैं जो अपने सर्वोत्तम मित्र भारत तक को अंदरूनी योजना के बारे नहीं बताते?

आज कितने लोगों को फरवरी 1979 की घटना याद है, जब तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन दौरे पर थे, और चीन ने वियतनाम को 'सबक सिखाने' के नाम पर उस पर हमला कर दिया -वाजपेयी इतना व्यथित हुए कि अपना दौरा बीच में छोड़कर आ गये। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस घटना पर 'गहरी प्रतिक्रिया और चिंता' व्यक्त की व भारत-चीन संबंध फिर से ठंडे पड़ गए।

बेशक, 47 साल बाद के हालात अलग हैं। जिस तरह भारत में ईरान के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने पर बहस चलती रही, उसी प्रकार ईरानी युद्धपोत 'डेना' को अमेरिका द्वारा तारपीडो से डुबोने पर प्रतिक्रिया देने में भारत को पांच दिन लग गए। वह ईरानी युद्धपोत, जो अंतर्राष्ट्रीय नौसैन्य बेड़ा प्रदर्शन में भाग लेने के बाद अभी-अभी भारतीय जल सीमा से बाहर निकला ही था। एक ऐसे देश के लिए, जो क्वाड का हिस्सा हो-जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वह खुद शामिल है- और जिसे इसपर गर्व हो कि वह दुनिया का इकलौता देश है, जिसके नाम पर एक महासागर है, इन दिनों उसकी राजधानी में एक अजीब सी खामोशी पसरी है, जो बहुत कुछ बयां करती है। दूसरी तरफ, शुक्र करें कि इस्राइलियों ने भारतीय प्रधानमंत्री को ईरान पर बमबारी के बारे में तब नहीं बताया जब वे तेल अवीव में थे- इससे मोदी को आखिर समझ आ जाना चाहिए कि सबसे अच्छे दोस्त भी कैसे अपने पत्ते छिपाकर रखते हैं और जरा भनक नहीं लगने लेते। या फिर, उस जीवंत भारतीय यहूदी समुदाय के बावजूद जो कुछ दशक पहले भारत से इस्राइल जाकर बस गया था और मानता है कि 'जहां इस्राइल उनकी पितृभूमि है वहीं भारत मातृभूमि', यह उक्ति प्रधानमंत्री ने नेसेट में अपने भाषण के दौरान इस्तेमाल की थी; या फिर यह कि भारत इस्राइली रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है -मोदी को पता होना चाहिए कि भारत को इस्राइल-अमेरिका के पवित्रतम दायरे में घुसने की इजाज़त नहीं।

इसीलिए आत्मनिर्भरता भारत के वजूद का आधार बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का इस धारणा को बढ़ावा देना हमें बताता है कि भारत को ईरान में लड़कियों के स्कूलों पर बमबारी करने वाली ताकतों के साथ बिना विचारे तालमेल रखने से गुरेज करना चाहिए। जब चीज़ें हाथ से निकल जाएं तो भारत को अपनी बात कहने से डरना नहीं चाहिए- भले ही हमारे भीतर भी स्याह कोने हों, जिसमें उन तालिबान प्रशासन के साथ दोस्ती भी शामिल है, जो पत्नी को बेरहमी से पीटने की इजाज़त देता है।

यह तथ्य है कि आज का भारत पहले की अपेक्षा अधिक मज़बूत है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रति व्यक्ति जीडीपी बेहतर है (2025 में लगभग 2,800 डॉलर, जबकि 2014 में मोदी द्वारा सत्ता संभालते वक्त यह 1,486 डॉलर थी), एक मज़बूत और जीवंत प्रवासी समुदाय है जो विदेशों में असर रखता है और पैसे घर भेजता है।

लेकिन बाहर एक अंधेरी दुनिया है और यह और अधिक अंधेरी होती जाएगी। आत्मनिर्भरता, गुट-निरपेक्षता, आप इसे जो भी कहें, भारत का एकमात्र मार्गदर्शक हो सकता है जो हमें रोशनी की ओर ले जाए।

प्रेरणा

भक्ति की पराकाष्ठा: जब भगवान भी भक्त के भरोसे खड़े हो गए

भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में भगवान और भक्त के संबंध को अत्यंत पवित्र और भावनात्मक माना गया है। यह संबंध केवल पूजा, आराधना या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण का गहरा भाव छिपा होता है। हमारे धर्मग्रंथों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जो यह बताते हैं कि जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान भी उसके सामने स्वयं को छोटा बना लेते हैं। रामायण में वर्णित श्रीराम और केवट का प्रसंग इसी सत्य को अत्यंत सरल और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस गहरे दर्शन को उजागर करती है जिसमें भक्ति और विनम्रता की शक्ति को समझा जा सकता है। जब भगवान श्रीराम को चौदह वर्ष का वनवास मिला और वे अयोध्या से सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब अनेक भावनात्मक घटनाएं घटित हुईं। अयोध्या से दूर निकलते हुए वे गंगा के तट पर पहुंचे। उन्हें आगे बढ़ने के लिए गंगा नदी पार करनी थी। वहां एक साधारण नाविक केवट अपनी नाव लेकर लोगों को नदी पार कराया करता था। जब श्रीराम ने उससे विनम्रता से कहा कि वह उन्हें नदी के पार पहुंचा दे, तब केवट ने तुरंत नाव ले आने के बजाय एक अनोखी बात कही। उसने कहा कि वह पहले भगवान के चरण धोना चाहता है, उसके बाद ही उन्हें नाव में बैठाकर नदी पार कराएगा। यह बात सुनकर आसपास खड़े लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन केवट के हृदय में भगवान के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम था, वही उसके शब्दों में झलक रहा था। उसने विनम्रता से कहा कि उसने सुना है कि भगवान के चरणों की धूल में अद्भुत शक्ति होती है। उसने अहिल्या के उद्धार का प्रसंग याद करते हुए कहा कि जब भगवान के चरणों की धूल पत्थर को भी जीवित कर सकती है, तो उसकी लकड़ी की नाव का क्या होगा। यदि भगवान के चरणों की धूल उसकी नाव पर पड़ गई और वह भी किसी अन्य रूप में बदल गई, तो उसकी रोजी-रोटी का साधन समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह चाहता था कि पहले भगवान के चरणों को अच्छी तरह धो लिया जाए।

भगवान श्रीराम ने केवट की इस सरल और निष्कपट भावना को समझ लिया। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। तब केवट ने एक छोटी सी कठौती में जल भरकर भगवान के चरण धोने शुरू किए। वह अत्यंत श्रद्धा और सावधानी से यह कार्य कर रहा था। जब वह भगवान का एक पैर धोता, तो उसे बाहर रख देता और फिर दूसरा पैर धोने लगता। लेकिन जैसे ही पहला पैर गीला होने के कारण जमीन पर रखा जाता, उस पर धूल लग जाती। तब केवट उसे फिर से उठाकर धोने लगता। इस प्रकार केवट बार-बार भगवान के चरणों को धोता रहा। उसके लिए यह केवल एक साधारण सेवा नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण था। वह चाहता था कि भगवान के चरण पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल रहें। उसके मन में यह भावना थी कि भगवान की सेवा करने का यह अवसर उसे बड़ी कृपा से मिला है और वह इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाना चाहता है। कुछ समय बाद केवट ने भगवान से विनम्रता से कहा, "प्रभु, यदि आप कृपा करके एक पैर कठौती में रख दें और दूसरा मेरे हाथ में रख दें तो चरणों में फिर से धूल नहीं लगेगी।" उसके शब्दों में अत्यंत सरलता और श्रद्धा थी। भगवान श्रीराम उसकी भक्ति को देखकर मुस्कुराए और मजाक में उससे पूछ बैठे, "केवट, अगर मैं एक पैर कठौती में और दूसरा तुम्हारे हाथ में रख दूं, तो कहीं मैं गिर नहीं जाऊंगा?" यह सुनकर केवट ने बहुत सहज भाव से उत्तर दिया, "प्रभु, आप चिंता क्यों करते हैं? आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, तब आप कभी नहीं गिरेंगे।" उसकी बात में इतनी आत्मीयता और विश्वास था कि उसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं थी। वह भगवान को किसी दूर बैठे देवता की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि अपने प्रिय अतिथि की तरह मानकर उनकी सेवा कर रहा था। भगवान श्रीराम ने भी उसी सहजता से केवट की बात मान ली। उन्होंने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख दिए और उसी प्रकार खड़े हो गए जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। उस क्षण का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। जिस भगवान को संसार का रक्षक माना जाता है, जो अपने भक्तों को हर संकट से बचाने वाले हैं, वही भगवान उस समय अपने भक्त के सहारे खड़े थे।

कुछ समय बाद श्रीराम ने केवट से मुस्कुराते हुए कहा, "भइया केवट, आज मेरे भीतर का एक अभिमान टूट गया है।" यह सुनकर केवट चकित हो गया। उसने विनम्रता से पूछा, "प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?" तब भगवान श्रीराम ने उत्तर दिया, "केवट, सच कह रहा हूं। अभी तक मेरे मन में यह भाव था कि मैं अपने भक्तों को गिरने से बचाता हूं और उन्हें सहारा देता हूं। लेकिन आज मुझे यह अनुभव हुआ कि भगवान को भी गिरने से बचाने के लिए भक्त के सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है।" भगवान के इन शब्दों में भक्ति का अत्यंत गहरा संदेश छिपा हुआ है। यह प्रसंग यह बताता है कि भगवान और भक्त का संबंध केवल पूजा या अनुष्ठानों से नहीं बनता, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से बनता है। जब किसी के हृदय में सच्ची भक्ति होती है, तो भगवान भी उसके सामने अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। केवट का यह व्यवहार केवल विनम्रता का उदाहरण नहीं था, बल्कि यह उस गहरे प्रेम का प्रतीक था जिसमें भक्त अपने भगवान को अपना मान लेता है। वह भगवान को दूर बैठे हुए किसी अलौकिक अस्तित्व के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा समझता है। यही कारण था कि उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम था। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि भगवान के लिए धन, वैभव या बाहरी आडंबर का कोई महत्व नहीं होता। भगवान केवल उस भाव को स्वीकार करते हैं जो भक्त के हृदय में होता है। केवट एक साधारण नाविक था, उसके पास देने के लिए कोई बड़ी वस्तु नहीं थी। लेकिन उसके पास सच्चा प्रेम और समर्पण था, जिसने भगवान को भी भावविभोर कर दिया। रामायण की यह कथा यह संदेश देती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को त्यागकर सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है, तब वह ईश्वर के और अधिक निकट पहुंच जाता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ को भूलकर केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान को याद करता है।

राष्ट्रपति का अपमान, क्या TMC ने इस बार सच में सारी हदें पार कर दी?

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक कॉन्फ्रेंस को लेकर विवाद गहरा गया है। बात इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी को घेरा है। राष्ट्रपति मुर्मू सिलीगुड़ी में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही थी। उसे लेकर उन्हें ममता दीदी से कुछ शिकायतें थी। इनके जवाब में ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति मुर्मू को बीजेपी का एजेंट बता डाला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आदिवासी समुदाय की अस्मिता से जोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे से जुड़ा विवाद केवल कार्यक्रम में व्यवस्था तक सीमित नहीं। यह मामला अब संवैधानिक गरिमा, प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी राजनीति का बन चुका है। राष्ट्रपति का खुद सार्वजनिक रूप से खामियों की ओर इशारा करना भी सामान्य बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नौवीं अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस थी। राष्ट्रपति मुर्मू इसमें शामिल होने आई थी। कॉन्फ्रेंस के वेन्यू को लेकर राष्ट्रपति ने ममता पर कटाक्ष कर दिया। उन्होंने शिकायत की कि वेन्यू बहुत छोटा था और वहां 5000 लोग भी शामिल नहीं हो सकते थे। इस वजह से बहुत सारे संथाल लोग कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए। वहां का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा जाके देखें यहां तो बहुत अच्छा है। इतना बड़ा फील्ड है। यहां तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। क्या मन में समाया है उनका वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूं लेकिन यहां आके बहुत खुश लगा कि वहां के लोग वहां भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति विधान नगर में एक दूसरे प्रोग्राम में पहुंची। वहां उन्हें जगह ज्यादा बड़ी लगी। इस पर उन्होंने सवाल किया कि यहां अगर कार्यक्रम होता तो 5 लाख लोग भी आ सकते थे। दूसरे कार्यक्रम में जो विधान नगर में था वहां जगह काफी पड़ी थी। वहीं जाकर प्रेसिडेंट ने कार्यक्रम स्थल को लेकर तंज कसे थे। राष्ट्रपति की नाराजगी इस बात पर भी थी कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के किसी मंत्री को होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें इस पर ऐतराज नहीं है लेकिन देश के राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाना चाहिए। ममता ने सवाल किया कि क्या यह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्लान है? क्या इसीलिए राज्यपाल को बदल दिया गया है? उन्होंने आरोप लगाया कि सीवी आनंद बोस को पूर्व उपराष्ट्रपति जयदीप धनकर की तरह डराधमका कर पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि बंगाल चुनाव के बाद उनका टारगेट दिल्ली होगा। अगर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वे सभी बीजेपी शासित राज्यों में जाएंगी और रैलियां कर पार्टी को खत्म कर देंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर रविवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि राज्य की जागरूक जनता एक महिला आदिवासी नेता और देश की राष्ट्रपति का 'अपमान' करने के लिए पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के कारण न केवल आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में कुप्रबंधन देखने को मिला, बल्कि यह राष्ट्रपति, संविधान और देश में लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। राष्ट्रपति मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के सम्मान में आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेने के लिए बंगाल गई थीं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार करना चुना, जिसका राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय दोनों के लिए बहुत महत्व है। उधर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से राज्य में राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा के दौरान हुए प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

ममता बनर्जी ने ऐसे बयान दिए जिनसे यह संकेत मिला कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। इससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया और राज्य एवं केंद्र के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही पत्र लिखकर बताया था कि संबंधित निजी संगठन राष्ट्रपति स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम नहीं है, इसके बावजूद राष्ट्रपति ने अपने विवेक से निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की व्यवस्था और उसमें आई कमियों के लिए आयोजक और एयरपोर्ट अथॉरिटी जिम्मेदार है, राज्य सरकार नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री हर चुनाव से पहले बंगाल को निशाना बनाते है और राज्य का अपमान करते है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में कोलकाता के मेयर मौजूद थे, जबकि वह खुद लोगों के अधिकारों को लेकर धरने में शामिल थी। ऐसे में मै वहा से कैसे जा सकती थी? ममता ने कहा कि धरना शुरू होने से पहले मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। मैं यहां लोगो की लड़ाई लड़ रही हूं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर किए गए मोदी के हमले का खंडन किया। अपने दावे के समर्थन में बनर्जी ने सीनियर बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बैठे हुए पीएम मोदी की एक बड़ी तस्वीर दिखाई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनके बगल में खड़ी हैं। यह तस्वीर कथित तौर पर मार्च 2024 के उस कार्यक्रम की है, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मु ने आडवाणी को उनके घर पर भारत रत्न से सम्मानित किया था।

अभियान

भक्त शिरोमणि मीराबाई: कृष्णभक्ति, समर्पण और दिव्य मिलन की अमर गाथा

भारतीय भक्ति परंपरा में अनेक संतों और भक्तों ने अपनी साधना और प्रेम से ईश्वर के प्रति समर्पण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो सदियों बाद भी लोगों के हृदय को प्रेरित करता है। इन महान भक्तों में मीराबाई का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उन्हें भक्त शिरोमणि कहा जाता है, क्योंकि उनकी कृष्णभक्ति केवल आराधना नहीं थी, बल्कि जीवन का संपूर्ण समर्पण थी। मीराबाई ने अपने जीवन के हर क्षण को श्रीकृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिया और अंततः वही प्रेम उनके दिव्य मिलन का कारण बना। उनकी भक्ति इतनी अनन्य और निष्कलंक थी कि यह माना जाता है कि वे स्वयं श्रीकृष्ण की मूर्ति में सशरीर समाहित हो गईं। भारतीय भक्ति परंपरा में यह घटना अद्वितीय मानी जाती है और आज भी श्रद्धालु इसे भगवान और भक्त के दिव्य मिलन का प्रतीक मानते हैं। सामान्यतः दुनिया में श्रीकृष्ण के साथ राधा की पूजा सर्वत्र की जाती है और दोनों के प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। किंतु राजस्थान के जयपुर के आमेर में स्थित जगतशिरोमणि मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां श्रीकृष्ण के साथ उनकी महान भक्त मीराबाई की पूजा की जाती है। यह परंपरा अपने आप में अनूठी है और इस बात का प्रमाण भी कि भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा का नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का होता है। इस मंदिर में श्रीकृष्ण और मीरा का विग्रह भक्तों को उस दिव्य कथा की याद दिलाता है जिसमें एक साधारण स्त्री ने अपनी भक्ति से स्वयं भगवान को अपने प्रेम में बांध लिया। मीराबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था। वे राजपरिवार में जन्मी थीं और उनके पिता रतनसिंह राठौड़ उस समय के प्रतिष्ठित शासकों में गिने जाते थे। राजसी वातावरण में पली-बढ़ी होने के बावजूद मीरा का मन बचपन से ही आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर झुका हुआ था। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटी थीं, तब उन्होंने एक बार अपनी माता से पूछा कि उनका विवाह किससे होगा। उनकी माता ने मुस्कुराते हुए श्रीकृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि वही उनके दूल्हे हैं। यह बात बालिका मीरा के मन में इतनी गहराई से बैठ गई कि उन्होंने जीवन भर श्रीकृष्ण को ही अपना पति और आराध्य मान लिया। बचपन से ही मीरा का मन भजन, कीर्तन और श्रीकृष्ण की पूजा में लगा रहता था। वे अपने आराध्य को केवल देवता के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्रियतम के रूप में देखती थीं। यही कारण था कि उनका प्रेम सामान्य भक्ति से अलग और अत्यंत गहरा था। समय के साथ उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, जो महान योद्धा राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के बाद मीरा मेवाड़ के राजमहल में रहने लगीं, लेकिन वहां भी उनका जीवन भक्ति और साधना से ही जुड़ा रहा। वे महलों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवनशैली से दूर रहकर श्रीकृष्ण के भजन गाने और मंदिरों में पूजा करने में अधिक आनंद अनुभव करती थीं। मीराबाई के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पति भोजराज का असमय निधन हो गया। इस घटना ने उनके जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। पति की मृत्यु के बाद राजपरिवार में उनकी स्थिति कमजोर हो गई और उन्हें कई प्रकार के विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजघराने की परंपराओं के अनुसार उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे पर्दे में रहें और सांसारिक मर्यादाओं का पालन करें, लेकिन मीरा का मन केवल श्रीकृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। वे खुले रूप से भजन गातीं, मंदिरों में जातीं और संतों के साथ सत्संग करतीं। यह सब राजपरिवार के कुछ लोगों को स्वीकार्य नहीं था।

कहा जाता है कि उनके विरुद्ध कई षड्यंत्र भी रचे गए। उन्हें भक्ति से रोकने के लिए कई बार उन्हें भयभीत करने और नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए गए। एक कथा के अनुसार उन्हें विष का प्याला भेजा गया, लेकिन मीरा ने उसे भी श्रीकृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया और उन्हें कोई हानि नहीं हुई। एक अन्य प्रसंग में उन्हें सांप से भरी टोकरी भेजी गई, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से फूलों की माला निकली। इन घटनाओं को भक्तों ने भगवान की कृपा और मीरा की अनन्य भक्ति का प्रमाण माना। मीराबाई के जीवन में उनके गुरु संत रैदास का विशेष महत्व था। संत रैदास ने उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्हें श्रीकृष्ण का एक विग्रह भी प्रदान किया। मीरा उस विग्रह को अपने साथ हर जगह रखती थीं और उसी को अपना आराध्य मानकर पूजा करती थीं। उनके लिए वह केवल पत्थर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं श्रीकृष्ण का सजीव स्वरूप था। इसी विग्रह के सामने बैठकर उन्होंने अनेक भजन रचे जो आज भी भारतीय भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। कहा जाता है कि मीराबाई ने अपने जीवन में दो श्रीकृष्ण विग्रहों की पूजा की। एक विग्रह अचल रूप में था और आज जयपुर के आमेर में स्थित जगतशिरोमणि मंदिर में स्थापित है। दूसरा विग्रह वह था जिसे मीरा अपने साथ रखती थीं और जिसे चल विग्रह कहा जाता है। यह विग्रह उनके साथ बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक रहा। लोकमान्यता के अनुसार जब मीराबाई अंततः श्रीकृष्ण में समाहित हुईं, तब यह चल विग्रह भी उनके साथ ही विलीन हो गया। आज लगभग पांच सौ वर्ष बाद भी उस विग्रह का कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे यह कथा और भी रहस्यमयी बन जाती है। जयपुर के आमेर में स्थित जगतशिरोमणि मंदिर आज भी मीरा और श्रीकृष्ण की इस अद्भुत भक्ति का सजीव प्रमाण है। यह मंदिर लगभग चार सौ वर्ष पहले महारानी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनवाया था। यह मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह तीन मंजिलों का है और इसके ऊपर बने शिखरों को अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया गया है। मंदिर का संगमरमर का तोरण द्वार, उसके दोनों ओर खड़े विशाल हाथी और भीतर स्थित गरुड़ मंडप इसकी भव्यता को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। मंदिर के पत्थरों पर हाथियों, घोड़ों और पुराणों के अनेक कथानकों का सुंदर चित्रण किया गया है। मंदिर के भीतर श्रीकृष्ण और मीराबाई का विग्रह स्थापित है और उनके सामने गरुड़ जी की प्रतिमा हाथ जोड़कर विराजमान है। ऐसा प्रतीत होता है मानो गरुड़ स्वयं इस दिव्य प्रेम और समर्पण को प्रणाम कर रहे हों। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहां श्रीकृष्ण अपनी पत्नी के साथ नहीं, बल्कि अपनी भक्त मीराबाई के साथ विराजमान हैं। यहां पूजा की परंपरा भी विशेष है। पहले श्रीकृष्ण और मीरा की पूजा होती है और उसके बाद भगवान विष्णु की। इसका कारण यह है कि मंदिर में श्रीकृष्ण और मीरा का विग्रह सामने है और उसके पीछे विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की वास्तुकला में दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहां नियमित रूप से भजन, कीर्तन और लोकसंगीत के माध्यम से मीरा और श्रीकृष्ण की भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहती है। जब मंदिर में मीरा के भजन गूंजते हैं तो वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। आज भी मीराबाई के भजन पूरे भारत में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनके भजनों में विरह की पीड़ा, प्रेम की गहराई और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। "पायो जी मैंने राम रतन धन पायो" और "मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई" जैसे भजन आज भी लोगों के हृदय को भावविभोर कर देते हैं। मीराबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई भय नहीं होता। जब मनुष्य अपने हृदय को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब संसार की कठिनाइयां भी उसके मार्ग को नहीं रोक पातीं। मीरा ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और विरोधों का सामना किया, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। इस प्रकार मीराबाई का जीवन केवल एक भक्त की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और समर्पण की ऐसी अमर गाथा है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि मीराबाई को भक्त शिरोमणि कहा जाता है और उनकी कृष्णभक्ति भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सदैव अमर रहेगी।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 'नारी गौरव संवाद और माता यशोदा अवॉर्ड वितरण' कार्यक्रम आयोजित

- महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील की प्रेरक उपस्थिति
- देश के सर्वांगीण विकास में महिलाओं का अमूल्य योगदान : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- "जब नारी शक्ति जागृत होती है, तब समाज और राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाती है"
- मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाशाली अग्रणी महिलाओं के साथ संवाद करके महिला उत्कर्ष के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की
- मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को 'माता यशोदा अवॉर्ड' से सम्मानित किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ तौर पर कहा कि राज्य और देश के सर्वांगीण विकास में महिला शक्ति का अमूल्य योगदान है। यह बात उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित 'नारी गौरव संवाद और माता यशोदा अवॉर्ड वितरण' कार्यक्रम में कही।

इस कार्यक्रम में राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिलाएं मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री ने इस समारोह में महिला कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक श्रेष्ठ स्वैच्छिक संस्था और एक श्रेष्ठ महिला कार्यकर्ता को 'गुजरात महिला विकास पुरस्कार' से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, राज्य के चार जोन में श्रेष्ठ कार्य करने वाली मुख्य सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को 'माता यशोदा अवॉर्ड' से भी नवाजा गया।

मुख्यमंत्री ने खेल, सामाजिक, रक्षा, उद्योग, कला-संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिला अग्रणियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद कर महिला उत्कर्ष के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और महिलाओं के कल्याण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लागू राज्य सरकार की प्रोत्साहक योजनाओं पर विस्तार से रोशनी डाली।

श्री भूपेंद्र पटेल ने यह भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' मंत्र के साथ महिलाओं के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाएं घर की चौखट लांघ कर कोई नया कार्य शुरू करती हैं, तब उनके सामने अनेक सामाजिक चुनौतियां खड़ी होती हैं। लेकिन, इन अवरोधों को पार कर सफल होने वाली महिलाएं देश की दूसरी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा की किरण बन जाती हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमी महिलाओं को समाज की असली 'रोल मॉडल' करार दिया।

गुजरात में नारी सशक्तिकरण के मॉडल पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से उन्होंने महिलाओं के उत्कर्ष के लिए अनेक नई पहलें करते हुए राज्य की अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की है। अभी राज्य में 2.70 लाख से अधिक सखी मंडल कार्यरत हैं। इन मंडलों के माध्यम से राज्य की लाखों बहनों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के साथ जोड़ा गया है। ये आंकड़े ही साबित करते हैं कि महिलाएं राज्य के आर्थिक निर्माण में मजबूत भागीदार हैं।

गुजरात की बेटियां विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना डंका बजाएं, इसके लिए राज्य सरकार की कटिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान संकाय के प्रति राज्य की अधिकतर बेटियों का रुझान बढ़ाने के लिए, सरकार ने 'नमो लक्ष्मी' 'नमो सरस्वती' जैसी क्रांतिकारी योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इन योजनाओं के तहत कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई के लिए छात्राओं को 50,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक की सहायता प्रदान कर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों के स्टार्टअप्स को समुचित प्रोत्साहन देकर राज्य में एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण किया है, जिसका लाभ अनेक महिला उद्यमियों को मिला है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाकर उन्हें 'जॉब सीकर' से 'जॉब गिवर' बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है।

उन्होंने विशेषकर 'होम-बेस्ड स्टार्टअप' का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि ऐसे घर-आधारित स्टार्टअप से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी समय में उन्हें उचित श्रेणी में शामिल करके और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

इस अवसर पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील ने राज्य की नारी शक्ति के योगदान की सराहना की। इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जब हम समाज को कुछ देते हैं, तभी सही मायने में हमें बहुत कुछ वापस मिलता है। महिलाओं में नैसर्गिक रूप से ही त्याग और समर्पण की भावना होती है। यह मंत्र महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक समर्थ बनाने के साथ ही समाज में उनके योगदान को एक नई पहचान देगा।

डॉ. वकील ने आगे कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि 'नारी गौरव संवाद' जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की समस्याओं और उनके सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचते हैं, जिससे इस दिशा में उचित सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने पद्मश्री अवॉर्ड प्राप्त करने वाली महिलाओं, नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत महिलाओं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं, खेल और कला जगत की विख्यात महिलाओं, शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहीं महिलाओं के अलावा राज्य की सांस्कृतिक हस्तकला से जुड़ी प्रतिभाशाली महिलाओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया।

इन नारी रत्नों ने भी राज्य सरकार के महिला कल्याण के दृष्टिकोण एवं आयोजन की सराहना की।

महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री राकेश शंकर ने स्वागत भाषण में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा दी। इस मौके पर एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) आयुक्त श्री रणजीत कुमार सिंह और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

मियागाम करजन स्टेशन पर 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण प्रगति पर

(जीएनएस)। बढ़ती यात्री संख्या तथा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मियागाम करजन रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण किया जा रहा है। यह नया फुट ओवर ब्रिज संरक्षा को और सुदृढ़ करेगा, यात्रियों के प्लेटफार्मों के बीच आवागमन को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा तथा मियागाम करजन रेलवे स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाएगा।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्तमान में इस फुट ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। नींव का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, संरचनात्मक स्तंभ स्थापित किए जा चुके हैं तथा गर्डर लॉन्चिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। वर्तमान में सीढ़ियों, डेक स्लैब और छत (रूफिंग) से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं।

मियागाम करजन रेलवे स्टेशन मध्य गुजरात का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है, जो आसपास के गांवों और कस्बों के लोगों के लिए एक प्रमुख आवागमन केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह स्टेशन करजन तथा आसपास के क्षेत्रों में स्थित मंदिरों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से त्योहारों और धार्मिक अवसरों के दौरान यहां यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

धार्मिक महत्व के साथ-साथ यह स्टेशन स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पादों तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं को वडोदरा और भरूच जैसे बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सहायक है, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को व्यापक व्यापारिक नेटवर्क तक पहुंच मिलती है। इसके अतिरिक्त, यह स्टेशन आसपास के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा अध्ययन के लिए आने-जाने वाले विद्यार्थियों के दैनिक आवागमन को भी सुगम बनाता है। यात्रियों की निरंतर आवाजाही से स्टेशन परिसर के आसपास संचालित छोटे व्यवसायों, विक्रेताओं और परिवहन सेवाओं को भी लाभ मिलता है।

युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को लाने के लिए 50 फ्लाइट्स का संचालन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी हालिया संघर्ष के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर सोमवार से लगभग 50 उड़ानों का संचालन शुरू किया गया है, ताकि संकटग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय यात्रियों को सुरक्षित और समय पर भारत लाया जा सके। मंत्रालय ने यह निर्णय मौजूदा सुरक्षा स्थिति और भारतीय एयरलाइंस की परिचालन क्षमता का ध्यान रखते हुए लिया है।

मंत्रालय के अनुसार, दुबई, मस्कट, अबू धाबी, फुजैरा और जेद्दा सहित पश्चिम एशिया के प्रमुख हवाई अड्डों से भारत के लिए उड़ान सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी। इन मार्गों पर एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा जैसी प्रमुख भारतीय एयरलाइंस उड़ानों का संचालन करेंगी। यह उड़ानें मुख्य रूप से उन यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जो अपने कार्य, अध्ययन या पारिवारिक कारणों से इस क्षेत्र में फंसे हुए थे और संकट के बीच सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एयर इंडिया ने 10 से 18 मार्च के बीच नौ प्रमुख रूटों पर 78 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने की योजना बनाई है। इससे पश्चिम एशिया से भारत आने वाले यात्रियों के लिए

सीटों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकेगी और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा। हाल ही में 7 मार्च को इस क्षेत्र से भारत आने वाली 51 उड़ानों में कुल 8,175 यात्री भारत पहुंचे थे। इसके अगले दिन 8 मार्च को एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा ने दुबई, अबू धाबी, रस अल खैमाह, फुजैरा, मस्कट और जेद्दा से 49 आगमन उड़ानों का संचालन किया। इस प्रकार केवल दो दिनों में हजारों भारतीय सुरक्षित रूप से देश लौट आए।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय एयरलाइंस क्षेत्र के अन्य हवाई अड्डों पर जमीनी स्थिति का निरंतर आकलन कर रही हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि किसी हवाई अड्डे पर अचानक यातायात बढ़ता है या स्थिति और तनावपूर्ण होती है, तो अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की जा सके। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो।

इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ उड़ानों के किराए पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अनावश्यक मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की समय-सारिणी और उपलब्ध सीटों की जानकारी के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस से नियमित संपर्क में रहें। इसके अलावा, यात्रियों को उड़ानों के लिए अग्रिम बुकिंग करने और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की भी सलाह दी गई है।

विशेष रूप से इस समय एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस ने अपने उच्च प्रबंधन को तैनात किया है, ताकि फ्लाइट संचालन, जमीन पर परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एयरलाइंस ने अपने पायलट और फ्लाइट क्रू को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे संकटग्रस्त क्षेत्र में उड़ानों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता और सुरक्षा मानकों का पालन करें। इसके साथ ही, मेडिकल इमरजेंसी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू किया गया है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि सभी एयरलाइंस ने अपने टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से यात्रियों को ताजगी जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था की है। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को उड़ानों की उपलब्धता, उड़ान समय और सुरक्षा से संबंधित जानकारी सीधे उपलब्ध कराना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी बदलाव या विलंब के मामले में तुरंत संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।

सुरक्षा स्थिति को देखते हुए मंत्रालय और एयरलाइंस ने यह भी सुनिश्चित किया है कि फ्लाइट संचालन के दौरान हवाई अड्डों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच पूर्ण समन्वय बना रहे। प्रत्येक उड़ान के लिए सुरक्षा और परिचालन का विस्तृत प्लान तैयार किया गया है, जिसमें हवाई अड्डों पर लैंडिंग, टैक्सीइंग, ईमरजेंसी सेवाएं और आपातकालीन प्रोटोकॉल शामिल हैं।

इस बीच, मंत्रालय ने यह आश्वासन भी दिया कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय यात्रियों की राहत के लिए किसी भी समय और जरूरत पड़ने पर और अतिरिक्त फ्लाइट्स की व्यवस्था की जा सकती है। सभी एयरलाइंस को आवश्यकतानुसार संसाधनों को तैनात करने और यात्रियों की संख्या और उड़ानों की मांग के अनुसार फ्लाइट्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

10 मार्च की अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस भटनी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर केंट-भटनी सेक्शन के देवरिया सदर-नूनखार स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कमीशनिंग के संबंध में नॉन इंटरलोकिंग कार्य के कारण अहमदाबाद अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस आंशिक निरस्त रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

आंशिक निरस्त ट्रेने

10 मार्च 2026 की ट्रेन सं.19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस भटनी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा भटनी-गोरखपुर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

11 मार्च 2026 की ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस भटनी स्टेशन से ऑरिजिनेट होगी तथा गोरखपुर - भटनी स्टेशन के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए 'सिक्सर': 12 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 15,000 प्रशंसकों को पहुँचाया मंजिल तक,1.50 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व किया अर्जित

(जीएनएस)। क्रिकेट के महाकुंभ और अहमदाबाद में आयोजित विश्व कप 2026 के हाई-प्रोफाइल फाइनल मैच के मद्देनज़र पश्चिम रेलवे ने अपनी परिचालन क्षमता और यात्री सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 08 मार्च, 2026 को खेले गए इस ऐतिहासिक मुकाबले के दौरान दर्शकों की अभूतपूर्व भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रणनीतिक रूप से 12 विशेष ट्रिप ट्रेनों का संचालन किया, जो न केवल लॉजिस्टिक दृष्टि से सफल रहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुईं।

इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से 15,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की तथा इन ट्रेनों में 100 प्रतिशत से अधिक ऑक्युपेंसी दर्ज की गई। इन ट्रेनों के संचालन से 1.50 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही अहमदाबाद-दिल्ली आश्रम, अहमदाबाद-नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी, अहमदाबाद-मुंबई-सेंट्रल वंदे भारत, गांधीनगर कैपिटल-मुंबई-सेंट्रल वंदे भारत, अहमदाबाद-दादर गुजरात मेल, अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस लोक शक्ति जैसे प्रीमियम ट्रेनों की ऑक्युपेंसी भी 100 प्रतिशत से अधिक रही।

यात्रियों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख केंद्रों को जोड़ने वाले विशेष रूटों पर ट्रेनों का संचालन किया। इन ट्रेनों को मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और पुणे जैसे प्रमुख स्टेशनों से सीधे अहमदाबाद के लिए चलाया गया।

कुल 6 विशेष ट्रेनें अहमदाबाद की ओर (प्रशंसकों को मैच के लिए ले जाने हेतु) तथा 6 विशेष ट्रेनें अहमदाबाद से वापसी (मैच के उपरांत यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने हेतु) संचालित की गईं। नियमित ट्रेनों की समय सारिणी को प्रभावित किए बिना इन विशेष सेवाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि यात्रियों को लगभग 'डोर-टू-डोर' जैसी सुविधा का अनुभव प्राप्त हो सके।

ट्रेनों में 100 प्रतिशत से अधिक की ऑक्युपेंसी यह दर्शाती है कि क्रिकेट प्रशंसकों के बीच इन विशेष सेवाओं की भारी मांग थी। रेलवे ने कुछ ट्रेनों में भी 'तत्काल' आधार पर अतिरिक्त कोच जोड़कर अधिकतम यात्रियों को समायोजित करने का भी प्रयास किया।

भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद और मुंबई के स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल (RPF) तथा वाणिज्यिक कर्मचारियों की तैनाती की गई। स्टेशनों पर विशेष सहायता डेस्क तथा बेहतर उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था की गई ताकि प्रशंसकों को मैच के उत्साह के बीच किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

विश्व कप के दौरान पश्चिम रेलवे की इस पहल ने न केवल हजारों प्रशंसकों की यात्रा को आरामदायक बनाया, बल्कि बड़े आयोजनों के दौरान रेलवे की त्वरित प्रतिक्रिया और प्रबंधन क्षमता को भी प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया।

उत्तराखंड सरकार ने 1.11 लाख करोड़ रुपये का विकासोन्मुख बजट पेश किया

(जीएनएस)। भराड़ीसैंण। उत्तराखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.41 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार ने इसे विकासोन्मुख, संतुलित और जनकल्याण आधारित बताया है। बजट का उद्देश्य उत्तराखंड में सतत विकास, रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं को विस्तार देना है।

मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की टीम ने सदन में बताया कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, डिजिटल शासन, पर्यटन, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। बजट के माध्यम से राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, राज्य का कुल राजस्व व्यय 64,989.44 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 46,713.77 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। पूंजीगत परिव्यय 18,152.73 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य की कुल अनुमानित प्राप्तियां 1,10,143.12 करोड़ रुपये आंकी गई हैं, जिसमें 67,525.77 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां और 42,617.35 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

राज्य की वित्तीय संरचना में राजस्व स्रोतों का विवरण भी स्पष्ट किया गया है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व 28.85 प्रतिशत, केंद्रीय करों में राज्यांश 19.39 प्रतिशत, करेतर राजस्व 6.35 प्रतिशत तथा केंद्र सरकार से अनुदान व सहायता 20.59 प्रतिशत योगदान करेगी। इसके अलावा लोक ऋण का हिस्सा 24.04 प्रतिशत, लोक लेखा शुद्ध 0.75 प्रतिशत और ऋण व अग्रिम की वसूली 0.03 प्रतिशत है।

बजट व्यय का वितरण भी विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। वेतन, भत्ते और मजदूरी जैसे अधिष्ठान व्यय पर 25.45 प्रतिशत खर्च होगा। पेंशन और अनुतोषित भुगतान के लिए 12.45 प्रतिशत, निवेश ऋण के लिए 9.08 प्रतिशत, ब्याज व लाभांश के लिए 8.87 प्रतिशत, सहायक अनुदान व राज्य सहायता के लिए 4.72 प्रतिशत तथा निर्माण कार्यों पर 12.49 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित किया गया है। अन्य मदों के लिए 26.95 प्रतिशत व्यय रखा गया है।

सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार से 1,027 करोड़ रुपये का अवस्थापना अनुदान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन के लिए 705.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड में 112.02 करोड़ रुपये तथा पर्यटन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये और कॉलोनाइजेशन प्रोत्साहन से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए 25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए 15 करोड़ रुपये, उभरती प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्रियान्वयन के लिए 10.50 करोड़ रुपये, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन और 'महक क्रांति' कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये रखा गया है।

बजट में 'हाउस ऑफ हिमालयाज', 'उत्तराखंड एवं भारत दर्शन', नदी तट विकास, 'आपदा सखी' योजना, ग्राम प्रहरी योजना, नशा मुक्ति केंद्र और विदेश रोजगार प्रकोष्ठ जैसी योजनाओं के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया है ताकि सामाजिक सुरक्षा और समग्र विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

बजट पेश करते हुए सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन से नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ डिजिटल गवर्नेंस और आधारभूत ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है।

बजट के प्रमुख आंकड़ों के अनुसार, कुल बजट आकार 1,11,703.21 करोड़ रुपये है। इसमें राजस्व व्यय 64,989.44 करोड़ रुपये, पूंजीगत व्यय 46,713.77 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिव्यय 18,152.73 करोड़ रुपये शामिल हैं। राज्य की कुल अनुमानित प्राप्तियां 1,10,143.12 करोड़ रुपये रखी गई हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बजट का उद्देश्य केवल वित्तीय प्रबंधन नहीं है, बल्कि इसे जनकल्याण, रोजगार सृजन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार का यह कदम उत्तराखंड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल महंगाई पर कोई बड़ा असर नहीं: निर्मला सीतारमण का भरोसा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सदन में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया तेजी का फिलहाल देश में महंगाई पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में मुद्रास्फीति पहले से ही अपेक्षाकृत निचले स्तर के करीब बनी हुई है और इस समय घरेलू स्तर पर महंगाई नियंत्रित बनी हुई है। लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया कि फरवरी के अंत से 2 मार्च के बीच भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 69.01 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80.16 डॉलर प्रति बैरल हो गई। इसके बावजूद वर्तमान महंगाई स्तर को देखते हुए उनका मानना है कि तेल कीमतों में इस उछाल का तत्काल प्रभाव सीमित रहेगा। उन्होंने सदन में कहा कि फिलहाल घरेलू बाजार में पर्याप्त उपाय और मौद्रिक स्थिरता के चलते आम जनता को महंगाई के बढ़ने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि का मध्यम अवधि में महंगाई पर असर कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें रुपये-डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति का प्रभाव उपभोक्ताओं तक पहुंचना और समग्र मुद्रास्फीति की दिशा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी तत्वों के संतुलित रहने पर घरेलू महंगाई पर इसका सीमित असर ही पड़ेगा। वित्त मंत्री ने Reserve Bank of India (RBI) की अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अगर कच्चे तेल की कीमतें आधार अनुमान से 10 प्रतिशत अधिक बनी रहती हैं और इसका पूरा प्रभाव घरेलू कीमतों पर पड़ता है, तो महंगाई दर में लगभग 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई जोखिम नहीं दिखाई दे रहा और भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई नियंत्रण में सक्षम है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में वायदा कारोबार में तेल की कीमतें 26 प्रतिशत से अधिक बढ़कर करीब 114.29 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसके चलते कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत में पर्याप्त उपायों और रणनीतियों के चलते इस उछाल का असर फिलहाल सीमित रहेगा। निर्मला सीतारमण ने सदन में यह भी बताया कि सरकार लगातार घरेलू बाजार में तेल और ऊर्जा की आपूर्ति पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेट्रोलियम कंपनियों की रणनीतियां और तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुशासनिक प्रबंधन से घरेलू उपभोक्ता पर असर को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दिया कि आवश्यकतानुसार घरेलू तेल भंडार और रणनीतिक भंडारण का उपयोग कर कीमतों को स्थिर बनाए रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने सदन में यह स्पष्ट किया कि महंगाई दर पर असर केवल तेल कीमतों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें अन्य खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुएं, कृषि उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय वस्तु बाजार और मुद्रा विनिमय दर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति के आंकड़े फिलहाल स्थिर हैं और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण ने सदन में यह भी बताया कि केंद्र सरकार लगातार मुद्रास्फीति पर निगरानी रख रही है और यदि आवश्यक हुआ तो नीतिगत कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार में तेल की कीमतों के अस्थिर होने की स्थिति में सरकार तैयार है और आवश्यकतानुसार उपाय किए जाएंगे ताकि आम जनता को महंगाई के दुष्प्रभाव का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में घरेलू तेल कीमतों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। सरकारी सब्सिडी, रणनीतिक भंडारण और सरकारी नीतियों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के पर्याप्त उपाय मौजूद हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार घरेलू महंगाई दर को नियंत्रित रखने के लिए लगातार निगरानी और प्रबंधन कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि भारत के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े और RBI की रिपोर्ट यह संकेत देती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल इस उछाल को झेलने में सक्षम है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि वैश्विक तेल कीमतें लंबे समय तक उच्च बनी रहती हैं, तो मध्यम अवधि में घरेलू महंगाई दर पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति स्थिर है।

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना

Tender Notice No. M247GLRSFRP CAB252637 Date: 07.03.2026. कार्य का नाम: 25 KV कनवेंशनल इलेक्ट्रीक लोको में अग्निरोधी FRP केब व अन्य सुविधाओं का प्रावधान **स्थान:** मु.का.प्र./दाहोद प. रेलवे कार्यालय **कार्य की अनुमानित लागत:** Rs. 9,55,04,100/- **बयाना राशि:** Rs.6,27,600/- **ई-निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समय:** ई-निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय 30-03-2026 को 14:30 बजे तक तथा ई-निविदा उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेगी । **निविदा सूचना तथा प्रपत्र उपलब्धता: www.ireps.gov.in / E-Tenders / Works / IR Electrical.**

Apex/17/1/500

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

सूरत में अरविंद केजरीवाल का भाजपा पर तीखा हमला बोले—गुजरात के किसान और युवा बदलाव के लिए तैयार

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के राजनीतिक माहौल में इन दिनों चुनावी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में Arvind Kejriwal के गुजरात दौरे ने राज्य की राजनीति को और गर्म कर दिया है। Aam Aadmi Party के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने दौरे के दूसरे दिन सूरत में आयोजित क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ Bharatiya Janata Party और विपक्षी Indian National Congress दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है और पिछले तीन दशकों से चली आ रही राजनीति से तंग आ चुकी है।

सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने जनता से सवाल किया कि आखिर कब तक लोग भ्रष्टाचार, पेपर लीक, टूटी सड़कों, गिरते पुलों और अस्पतालों में बच्चों की मौत जैसी घटनाओं पर चुप रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में पिछले 30 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी आम लोगों की मूलभूत समस्याएं खत्म नहीं हुईं। उनके अनुसार राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई समस्याएं अब भी गंभीर रूप से मौजूद हैं।

केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि जिस तरह विसावदर की जनता ने हाल के चुनावों में बड़े-बड़े नेताओं के राजनीतिक सिंहासन को हिला दिया, उसी तरह अब पूरे गुजरात में बदलाव की लहर पैदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है और जब लोग एकजुट होकर फैसला करते हैं तो सबसे मजबूत सरकारें भी बदल जाती हैं।

अपने संबोधन में उन्होंने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात के किसान इस समय बेहद नाराज और आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कई इलाकों में किसानों से बातचीत के दौरान एक ही बात सुनने को मिल रही है कि वे इस बार चुनाव में अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि किसानों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उनसे ग्रामीण इलाकों में गहरा असंतोष पैदा हुआ है।

उन्होंने विशेष रूप से बोटाद जिले की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ समय पहले वहां किसान करदा प्रथा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनके अनुसार किसान केवल अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे थे और उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और कई किसानों को उनके घरों से पकड़कर जेल भेज दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि

लगभग 85 किसानों को कई महीनों तक जेल में रखा गया, जिससे पूरे किसान समुदाय में गुस्सा फैल गया।

केजरीवाल ने कहा कि किसानों का आरोप है कि वर्षों से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को मिलने वाले बीज, खाद, पानी और आर्थिक सहायता में भी भ्रष्टाचार हुआ है। उनके अनुसार कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं रही हैं, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में असंतोष बढ़ा है।

सभा के दौरान उन्होंने राज्य में बेरोजगारी और युवाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के हजारों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब युवा रोजगार की मांग करते हैं तो उन्हें ठोस अवसर देने के बजाय अन्य समस्याओं में उलझा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने रोजगार और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

केजरीवाल ने राज्य में नकली शराब और नशे के बढ़ते खतरे का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की समस्या गंभीर होती जा रही है और इसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर देने के बजाय अगर उन्हें नशे के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होना पड़े, तो यह समाज और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है।

अपने भाषण में उन्होंने राज्य में हुए कुछ बड़े हादसों का जिक्र करते हुए सरकार की आलोचना की। केजरीवाल ने कहा कि कुछ साल पहले मोरबी में पुल गिरने की घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे केवल दुर्घटनाएं नहीं होते, बल्कि यह व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितनी घटनाओं के बाद सरकार बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और गुणवत्ता पर गंभीरता से काम करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि जब एक गरीब किसान अपनी जमीन या परिवार के गहने बेचकर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजता है, तो उसके मन में यह उम्मीद होती है कि उसका बच्चा मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन जब परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं तो उस छात्र और उसके परिवार की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके।

सभा के अंत में केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर लोग वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें नई राजनीतिक दिशा चुननी होगी। उन्होंने कहा कि जब जनता की सरकार बनती है तो फैसले भी जनता की भलाई को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी को मौका मिलता है तो राज्य में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में वहां की सरकार ने बजट में महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि इसी तरह की योजनाएं गुजरात में भी लागू की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए जनता को राजनीतिक बदलाव का फैसला करना होगा।

अपने संबोधन के अंत में केजरीवाल ने लोगों से कहा कि गुजरात केवल किसी एक पार्टी या परिवार की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह राज्य यहां रहने वाले हर नागरिक का है। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग मिलकर राज्य के विकास और भविष्य के बारे में सोचें तो गुजरात को एक बेहतर और सुरक्षित दिशा दी जा सकती है। उनके अनुसार आने वाले समय में राज्य की राजनीति में जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और वही तय करेगी कि गुजरात किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

टीम इंडिया ने अहमदाबाद में रचा इतिहास: धोनी ने गंभीर और बुमराह की जमकर तारीफ की

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे पलों में से एक शनिवार को अहमदाबाद में दर्ज किया गया, जब भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर दुनियाभर में अपनी झलक दिखा दी। इस शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS Dhoni ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टीम और सपोर्ट स्टाफ को बधाई दी। महेंद्र सिंह धोनी ने खास तौर पर टीम के मुख्य कोच Gautam Gambhir और तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah की तारीफ की, जिससे क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्साह और भी बढ़ गया। धोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, "अहमदाबाद में इतिहास रचा गया। टीम, सपोर्ट स्टाफ और दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी फैंस को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई।" उनके इस पोस्ट में न केवल टीम की तारीफ थी बल्कि पूरे क्रिकेट परिवार और फैंस को सम्मान देने की झलक भी दिखाई दी।

महेंद्र सिंह धोनी ने कोच गौतम गंभीर के बारे में लिखा, "कोच साहब, आपकी मुस्कान आप पर बहुत अच्छी लग रही है। जोश और मुस्कान का मेल कमाल का है, बहुत बढ़िया।" इस कमेंट से स्पष्ट हुआ कि धोनी केवल टीम के प्रदर्शन से ही नहीं, बल्कि स्टाफ के सकारात्मक रवैये और नेतृत्व शैली से भी प्रभावित हैं।

साथ ही उन्होंने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन की भी सराहना की। फाइनल मुकाबले में बुमराह की गेंदबाजी ने विपक्षी टीम न्यूजीलैंड की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। इस पर धोनी ने लिखा, "बुमराह के बारे में कुछ न लिखूं तो ही अच्छा है, चैंपियन बॉलर।" धोनी का यह कमेंट बुमराह के दबाव में भी शांत और सटीक प्रदर्शन की ओर इशारा करता है।

भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए और फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 159 रन पर रोक दिया। यह स्कोर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा टोटल भी बन गया।

इस जीत के साथ टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। यह भारत की लगातार दूसरी टी20 वर्ल्ड कप जीत है और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में तीन बार खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम भी बन गई है। साथ ही, कोई मेजबान देश पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का गौरव हासिल किया। अहमदाबाद में खेली गई यह जीत न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरी देशवासियों के लिए गर्व का क्षण थी।

धोनी की प्रतिक्रिया में टीम की रणनीति, मानसिक मजबूती और खेल भावना की भी झलक मिली। उन्होंने फैंस को याद दिलाया कि इस जीत में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट टीम की मेहनत भी शामिल है। उनके कमेंट्स से स्पष्ट होता है कि टीम के भीतर सकारात्मक वातावरण और सहकर्मी भावना ने टीम को विश्व विजेता बनने में मदद की।

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पक्षों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए, टीम इंडिया ने 255 रन का विशाल स्कोर बनाया। कप्तान और बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। इसके बाद गेंदबाजी में भी टीम ने न्यूजीलैंड को कोई मौका नहीं दिया। बुमराह, चहल और अन्य गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को अच्छी तरह नियंत्रित किया, जिससे टीम को यह ऐतिहासिक जीत मिल सकी।

धोनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस जीत में युवा खिलाड़ियों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं ने भी अपने प्रदर्शन से महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह संतुलन और टीम भावना ही भारत की सबसे बड़ी ताकत रही है।

सामाजिक और डिजिटल मीडिया पर भी इस जीत का जोश देखा जा सकता है। धोनी के पोस्ट ने फैंस के बीच खुशी और उत्साह की लहर दौड़ा दी। उनके कमेंट्स ने टीम की जीत को सिर्फ खेल के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भावनात्मक और राष्ट्रीय गर्व के नजरिए से भी महत्वपूर्ण बना दिया।

इस शानदार जीत ने न केवल खिलाड़ियों के नाम बल्कि भारत के क्रिकेट इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। टीम इंडिया का यह प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गया है और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए उच्च मानक तय किया है।

फाइनल मुकाबले के बाद भारत में जश्न का माहौल था। क्रिकेट फैंस ने अहमदाबाद और देशभर में भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत का आनंद लिया। धोनी की प्रतिक्रिया ने इस जश्न में चार चांद लगा दिए और उनके कमेंट्स ने टीम के अंदर की ताकत और सकारात्मकता को दुनिया के सामने पेश किया।

राजकोट के भडली गांव में सेवा सेतु कार्यक्रम 17 गांवों को सरकारी सेवाओं से जोड़ा गया

(जीएनएस)। राजकोट जिले के विंछिया तालुका के भडली गांव में राज्य सरकार की पहल "सेवा सेतु – सरकार आपके द्वार" का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया, जिसमें 17 गांवों के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सीधे ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर से बचाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार तथा ग्रामीण विकास मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने की। इस अवसर पर मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के हर तालुका में सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से अब ग्रामीण लोग अपने गांव में ही सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और उन्हें दूर-दराज के कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा सेतु कार्यक्रम से सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ रही है और नागरिकों को लाभ उठाने में सुविधा मिल रही है।

सेवा सेतु कार्यक्रम में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अपडेट, पेंशन से जुड़े आवेदन, श्रमयोगी कार्ड, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित अनेक सरकारी सेवाओं

के लिए मार्गदर्शन और आवेदन की सुविधा प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह पहल काफी उपयोगी साबित हो रही है क्योंकि इससे लोगों की सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है और अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

भडली में आयोजित इस कार्यक्रम में भडली, बंधाली, देवधरी, सनाली, मोढुका, फुलजर, सनाला, वनाला, सोमलपर, कांसलोलिया, गढला, बेलड़ा, सरतानपर, सोमपिपलिया, पाटियाली, आंकड़िया और वेरावल-भाडली सहित कुल 17 गांवों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दिया और उनके आवेदन लेने में मदद की।

कार्यक्रम में रेवेन्यू, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एवं पशुपालन, सोशल फॉरेस्ट्री, ICDS, महिला एवं बाल विकास, सप्लाई, श्रम एवं रोजगार सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इन विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की जरूरतों के अनुसार उनके आवेदन और शिकायतों का निस्तारण किया। जसदन प्रांत अधिकारी राहुल खंभारा, विंछिया प्रांत अधिकारी उत्तम कानाणी, तालुका विकास अधिकारी पार्थराजसिंह परमार समेत अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इस कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए ग्रामीणों से संवाद किया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं से जोड़ना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से दिलाना था। इसके अलावा, यह पहल सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर रही है। ग्रामीण लोग अब बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपने प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

भडली गांव में आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम ने ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ाया है। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इससे उनकी जिंदगी आसान हुई है। वे अब अपने गांव में ही सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और उन्हें किसी दूरस्थ कार्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और सरकारी विभागों के साथ सहयोग करें। मंत्री ने यह भी कहा कि सेवा सेतु कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कृषि संबंधित सेवाओं में सहायता मिल रही है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो रहा है।

भडली में आयोजित इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक ही मंच पर मौजूद थे। ग्रामीणों के आवेदन और शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया, जिससे लोगों को वास्तविक समय में लाभ मिला। इस प्रकार का समेकित कार्यक्रम ग्रामीण प्रशासन और जनता के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करता है। राज्य सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना अब सिर्फ कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में ही उन्हें सीधे लाभ मिल रहा है। इससे ग्रामीण लोग सरकारी सेवाओं का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और प्रशासन के साथ सीधे संवाद कर अपनी जरूरतों को व्यक्त कर सकते हैं।

वडोदरा से मुंबई तक 108 एयर एम्बुलेंस से मरीज का सुरक्षित एयरलिफ्ट, विशेषज्ञों की निगरानी में जारी इलाज

(जीएनएस)। वडोदरा। शहर की 108 एयर एम्बुलेंस सेवा ने एक गंभीर मेडिकल मामले में समय पर और सुरक्षित कदम उठाते हुए हिनाबेन जितेंद्रभाई ठक्कर (68) को वडोदरा से मुंबई तक एयरलिफ्ट किया। हिनाबेन का इलाज वडोदरा के भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन अस्थमा और सांस लेने में गंभीर परेशानी के चलते डॉक्टरों ने उन्हें उन्नत चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी।

मरीज की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल निर्णय लिया गया कि वडोदरा से मुंबई तक एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से ट्रांसफर किया जाए। इस दौरान 108 एयर एम्बुलेंस में विशेषज्ञ मेडिकल टीम मौजूद रही, जिन्होंने पूरे मार्ग में हिनाबेन की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखी। एयर एम्बुलेंस को इस तरह से तैयार किया गया कि उसमें जीवन रक्षक उपकरण, मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य जरूरी मेडिकल सुविधाएं मौजूद थीं। इस व्यवस्था ने सुनिश्चित किया कि मरीज का स्थानांतरण पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से हो।

108 सेवा के अधिकारियों ने बताया कि एयरलिफ्ट के दौरान मरीज की नाड़ी, रक्तचाप, ऑक्सीजन स्तर और सांस लेने की स्थिति की लगातार जांच की गई। मेडिकल टीम ने हर समय यह सुनिश्चित किया कि मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा या जोखिम का सामना न करना पड़े। इस तरह की तत्काल और व्यवस्थित कार्रवाई ने मरीज और परिवार को राहत प्रदान की।

हिनाबेन को मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल

में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है और उन्हें आवश्यक उपचार और निगरानी मिल रही है। परिवार ने 108 सेवा और मेडिकल टीम की तत्परता की प्रशंसा की, क्योंकि समय पर एयरलिफ्ट ने हिनाबेन की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

108 इमरजेंसी सेवा, राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में देखी जाती है। गंभीर परिस्थितियों में यह सेवा मरीजों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है, जिससे समय पर इलाज संभव होता है और जान बचाने के मौके बढ़ जाते हैं। हिनाबेन का यह मामला इसके बेहतरीन उदाहरण के रूप में सामने आया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, गंभीर श्वसन संबंधी रोगों में समय पर उन्नत अस्पताल में पहुंचना मरीज की जीवन रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट से न केवल मरीज की हालत पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्रवाई भी की जा सकती है।

108 एयर एम्बुलेंस सेवा का यह मिशन यह भी स्पष्ट करता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा सकती है। वडोदरा से मुंबई तक हिनाबेन का एयरलिफ्ट इस बात का प्रमाण है कि जब तकनीक, विशेषज्ञता और तत्परता एक साथ आती हैं तो गंभीर मेडिकल स्थितियों में भी सफलता संभव है।

हिनाबेन के परिवार ने कहा कि यदि यह एयरलिफ्ट व्यवस्था न होती तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जातीं। उन्होंने अस्पताल और 108 सेवा की तत्परता की जमकर सराहना की और बताया कि हर मरीज के लिए इस तरह की सुविधा जीवन रक्षक साबित हो सकती है।

क्रूड ऑयल वायदा में 1213 रुपये का ऊछाल: सोना वायदा 1384 रुपये और चांदी वायदा 4969 रुपये लुढका

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 237118.29 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 44698.23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 192418.64 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 39702 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 11262.48 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 17406.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 160651 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 161511 रुपये और नीचे में 159826 रुपये पर पहुंचकर, 161634 रुपये के पिछले बंद के सामने 1384 रुपये या 0.86 फीसदी गिरकर 160250 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 1145 रुपये या 0.87 फीसदी गिरकर 131221 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 137 रुपये या 0.82 फीसदी गिरकर 16510 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 160489 रुपये के भाव पर खूलकर, 161550 रुपये के दिन के उच्च और 159400 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1388 रुपये या 0.86 फीसदी गिरकर 160346 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 162001 रुपये के भाव पर खूलकर, 162398 रुपये के दिन के उच्च और 160621 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 162621 रुपये के पिछले बंद के सामने 1339 रुपये या 0.82 फीसदी गिरकर 161282 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 267497 रुपये के भाव पर खूलकर, 267498 रुपये के दिन के उच्च और 260743 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 268285 रुपये के पिछले बंद के सामने 4969 रुपये या 1.85 फीसदी गिरकर 263316 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 5528 रुपये या 2.01 फीसदी लुढ़ककर 269097 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 5398 रुपये या 1.96 फीसदी गिरकर 269398 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 2472.49 करोड़ रुपये के

कमोडिटी वायदाओं में 44698.23 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 192418.64 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 17406.17 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39702 पॉइंट के स्तर पर

ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 12.2 रुपये या 1.02 फीसदी घटकर 1185 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 3.15 रुपये या 0.97 फीसदी की बढ़त के साथ 327 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 5 पैसे या 0.01 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 339.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 65 पैसे या 0.34 फीसदी टूटकर 188.4 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 24673.94 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 8499 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 10549 रुपये और नीचे में 8499 रुपये पर पहुंचकर, 1213 रुपये या 14.5 फीसदी की तेजी के संग 9576 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 1215 रुपये या 14.53 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 9578 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 307.4 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 322.9 रुपये और नीचे में 303.3 रुपये पर पहुंचकर, 295.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 13 रुपये या 4.4 फीसदी की तेजी के संग 308.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 12.5 रुपये या 4.22 फीसदी बढ़कर 308.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 944.7 रुपये पर खूलकर, 1.8 रुपये या 0.19 फीसदी गिरकर 970 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11335.42 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 6070.75 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1193.81 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 805.73 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 10.30 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 462.65 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 20078.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 4578.63 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9702 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61156 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 30701 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 427559 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61348 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6982 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18788 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 67744 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 24118 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 22591 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 39383 पॉइंट पर खूलकर, 39850 के उच्च और 39356 के नीचले स्तर को छूकर, 319 पॉइंट बढ़कर 39702 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 594.9 रुपये की बढ़त के साथ 930 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 9 रुपये की बढ़त के साथ 24.25 रुपये हुआ।

सोना मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 8 रुपये की गिरावट के साथ 221.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 350000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 192 रुपये की गिरावट के साथ 1736 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.78 रुपये की गिरावट के साथ 21 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.49 रुपये की बढ़त के साथ 6.49 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 438.6 रुपये की गिरावट के साथ 762.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.6 रुपये की गिरावट के साथ 27.7 रुपये हुआ।

सोना मार्च 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 138 रुपये की बढ़त के साथ 403.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 507.5 रुपये की बढ़त के साथ 1970.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.88 रुपये की बढ़त के साथ 14.67 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 92 पैसे की नरमी के साथ 3.2 रुपये हुआ।